report of the Commission has already been placed in the Parliament Library for the information of the Hon'ble Members of Pariament.

**Admission of students migrated from Kashmir to Delhi educational institution**

**142.** SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any instructions have been issued to Delhi educational institutions for admission of students who have migrated from Kashmir; if so, what are the details thereof;

(b) what is the number of applications received from students of Engineering Colleges for transfer to colleges in Delhi;

(c) what action has been taken so far and proposed to be taken in this regtrd; and

(d) what is the number of such applications which have been received for transfer to colleges to states, other than Delhi, State-wise and what are the guide-lines issued to the State Governments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) to (d) In view of the prolonged disturbances in the Kashmir Valley, the Government decided to allow transfer of students from the Regional Engineering College (REC), Srinagar to other engineering colleges in the country. All States and Union Territories including Delhi were requested to accommodate their students studying in the REC, Srinagar in their own Engineering Colleges. The RECs in various States were advised to accommodate the students belonging to Jammu and Kashmir, foreign students and students from educationally deficient States studying in the REC, Srinagar. The States/Union Territories and the RECs have initiated action in the matter.



**Statement of vice-chief of Naval staff reffardm$_{ff}$ surveilliance/vigllance at Palk Straits**

143. SHRiI RAJU BHAI A PARMAR: SHRIMATI SATYA BAHIN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Indian Navy has asked the Government *to* lay down a clear policy, subject to surveillance/ vigilance on the Palk Strait especially in view of increased hostility between LTTE militants and the security force* in mid June this year as reported in the Indian Express dated 16th June, 1990; and

(b) if so, what was the precise suggestions made and Government's response thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) and (b) Government of India, being fully aware of the need for surveillance in the Palk Strait, had issued orders on the 30th May, 1990, inter alia, instructing the Navy and the Coast Guard to increase their surveillance/patrolling in the area in a coordinated manner so as to curb any unlawful activity across the Indian-Sri Lanka International Boundary Line. The Navy and the Coast Guard have accordingly stepped up their surveillance/patrolling in the area. The Naval Headquarters have informed that the news-paper item in question has not reported the facts correctly.

**मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम**

144. श्री अजीत जोगी :
श्री सुशील बरोंगपा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कायरत गैर-सरकारी

और स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) इन संस्थाओं को प्रतिवर्ष दी जा रही वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इनके कार्य का मूल्यांकन किया जा रहा है; यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 6 स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान संस्वीकृत किया गया है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन्हें वर्षानुसार दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :-

| वर्ष | स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या | परियोजना का आकार | संस्वीकृत अनुदान |
|---|---|---|---|
| 1987-88 | 1 | 600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र | 19,20,000/- |
| 1988-89 | 3 | 660 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र | 21,00,000/- |
| 1989-90 | 3 | 663 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र | 22,62,160/- |

(ग) जी हां, 1987-88 के दौरान संयुक्त मूल्यांकन दल जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि तथा एक गैर-सरकारी सदस्य था, ने 1986-87 के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्य का मूल्यांकन किया । यह पाया गया था कि

(i) दो स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य संतोषजनक था;

(ii) एक स्वैच्छिक एजेंसी का कार्य संतोषजनक पाया गया था, परंतु उसमें सुधार की आवश्यकता थी;

(iii) दो स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया था क्योंकि एजेंसी बड़ी परियोजना कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं थी;

(iv) एक स्वैच्छिक एजेंसी का कार्य असंतोषजनक पाया गया था;

(v) पांच स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य न केवल असंतोषजनक पाया गया था अपितु उनकी प्रमाणिकता पर भी शंका थी ।

**Setting up of regional offices of Administrative staff College**

145. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Administrative Staff Colleges of India has recommended setting up of more regional offices;

(b) if so, where and by when these regional centres have been proposed to be set up; and

(c) what would be infrastructure of these centres?

THE MINISTER OP STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Gadgil formula**

146. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have dropped the idea of amending the

Gadgil formula for the disbursement of funds amongst the States;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the Gadgil formula have been suitable; and

(d) whether the former Deputy Chairmen of the Planning Commission had assured, the members that Government would amend the Gadgil formula:?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER! OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) to (c) The disbursement of Central assistance for State Plans has so far been based on the modified Gadgil Formula as approved by the National Development Council in 1980. There have been suggestions for modification which are under examination in the context of the Eighth Plan formulation. The formula could be modified only with the approval of National Development Council.

(d) *Yea,* Sir. Th5 former Depuly Chairma:m of the Planning Commission had stated in the recently held N.D.C. meeting that as situation changed, conditions changed and hence it would be necessary to consider the various suggestions made in respect of modification in the formula.

**गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत वाराणसी में व्यय**

147. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 22 मई, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1379 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा में प्रदूषण को रोकने संबंधी कार्य योजना पर वाराणसी में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसमें कहां तक सफलता मिली है;

(ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत और कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है और क्या सरकार ने अब तक इस योजना की सफलता के संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय):** (क) से (ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत वाराणसी में 41.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 35 स्कीमें मंजूर की गई हैं। जून, 1990 तक 34.31 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मंजूर की गई 35 स्कीमों में से, 25 स्कीमें अब तक पूरी की जा चुकी हैं, जिसमें 7 अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीमें और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डी.एल.डब्ल्यू.) में 2 सीवेज उपचार संयंत्र की स्कीमें शामिल हैं। तीन अल्प-लागत सफाई से संबंधित स्कीमें, जिसमें 62 सामुदायिक शौचालय परिसर तथा 670 पोर फ्लश शौचालय शामिल हैं, पूरी की जा चुकी हैं। गंगा नदी में प्रतिदिन बहने वाले 25 मिलियन अपशेष जल का अवरोधन करके उसकी दिशा बदली गई है और उपचारित किया गया है। घुलित आक्सीजन (डी.ओ.) तथा बायोकेमिकल आक्सीजन मांग (बी. ओ. डी.) के सन्दर्भ में वाराणसी में जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 1986 में घुलित आक्सीजन (डी.ओ.) का स्तर जोकि 5.87 मिलीग्राम प्रति लीटर (एम.जी./एल.) था, वह 1989 में मिलीग्राम प्रतिलीटर (एम. जी./एल.) तक पहुंच गया तथा उसी अवधि में बायोकेमिकल आक्सीजन मांग (बी. ओ.डी.) का स्तर 10.60 मिलीग्राम प्रतिलीटर (एम.जी./एल.) से कम होकर 3.95 मिलीग्राम प्रतिलीटर (एम. जी./एल) तक हो गया है। गंगा कार्य योजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गंगा परियोजना निदेशालय ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (नीरी) नागपुर, और गंगा

कार्य योजना के प्रभाव का मूल्यांकन तैयार करने के लिए अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य-विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.पी.एच.) कलकत्ता की स्थापना की है। इस अध्ययन की अवधि दिसम्बर, 1988 से आरम्भ होकर तीन वर्ष की है और यह गंगा कार्य योजना की लागतों और लाभों का हिसाब रखने से संबंधित है जोकि वाराणसी और पश्चिम बंगाल में नवद्वीप में समुदाय के इंजीनियरी और स्वास्थ्य लाभों के विशेष सन्दर्भ में है।

**रक्षा आयुध फैक्टरियों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग**

148. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रक्षा आयुध फैक्टरियां अपनी-अपनी अधिष्ठापित क्षमताओं का पूरा उपयोग कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता के कितने प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) इनकी पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राजा रमन्ना)** : (क) और (ख) 1989-90 में आयुध निर्माणियों में वर्ष के दौरान उपयोग की गई कुल क्षमता कर्मचारियों के काय करने के मानक घंटों के रूप में 100.09 प्रतिशत थी।

(ग) इस सम्बंध में किए गए उपायों ये शामिल हैं :-

1. रेलवे, केन्द्रीय और राज्य पुलिस एवं सुरक्षा बलों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि जैसे गैर-रक्षा प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित मदों के निर्माण के क्षेत्रों में हाथ बढ़ाना और

2. आयुध निर्माणी के उत्पादों का विदेशों को निर्यात करना।

(घ) जी, नहीं। क्षमता का कम उपयोग तथा ऊपर भाग (ग) में उल्लिखित उपायों से उस क्षमता का उपयोग होने से फालतू क्षमता में कमी आने की संभावना को देखते हुए सरकार इस उद्देश्य के लिए कोई विशेषज्ञ समिति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझती।

**Misuse of National Museum Premises**

149. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR; SHRIMATI SATYA BAHIN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Museum was recently used as a venue for holding **a** lavish party in which drinks were freely served; and

(b) if so, the details thereof and the authority which permitted misuse of this important Institute; and

(c) what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMAN-*BHAi* MEHTA), (a) and (b) Yes, Sir. The open court-yard of the National Museum wag used as the venue by the Messile Lunch, New York to host a reception for the participants of the Asian Development Bank on 3rd May, 1990. Director General, National Museum permitted the holding of the reception after obtaining verbal clearance of the Department in August, 1989.

(c) Instructions are being issued to ensure that no alcoholic drinks are served in any function held in prestigious institutions like the National Museum. 13 Noon

## ANNOUNCEMENT ABOUT ACCEPTANCE OF RESIGNATIONS OF MEMBERS

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): What has happened to the allegations made by the former Deputy Prime Minister in regard to Bofors? Is a fresh committee going to be appointed?

MR. CHAIRMAN: I have to inform the House that I had received letters from Shri Virendra Verma, Member representing the State of Uttar Pradesh, and Shri Krishan Kumar Deepak, Member representing the State of Haryana, resigning their seats in Rajya Sabha. I had accepted their resignations with effect from 14th June, 1990 and 13th July, 1990 respectively.

Proclamation under Article 356 of the Constitution. Shri Subodh Kant Sahay.

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Is Mr Deepak going to be the nfrw Chief Minister of Haryana?

## PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION

THE MINSITER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): I beg $t_0$ lay $o_n$ the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers—

(i) Proclamation [G.S.R. No. 647-(E)] issued by the President on 18th July, 1990, under article 356 of the Constitution, in relation to the State Jammu and Kashmir, under clause (3) of the said 3article.

(ii) Order [GSR No. 648(E)] dated the 18th July, 1990, made by the President, under sub-clause (i) of clause (c) of the above Proclamation.

(iii) Report of the Governor of Jammu and Kashmir dated the 3rd July, 1990, to the President, recommending the issue of the Proclamation. [Placed in Library. *See* No. LT-1153/90],

## PAPERS LAID ON THE TABLE

Bills passed by the Houses of Parliament during the Hundred and Fifty-fourth Session of the Rajya Sabha and assente^ to by tjie President

SECRETARY-GENERAL: I beg to $la_v$ on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Bills passed by the Houses of Parliament during the Hundred and Fifty-fourth Session of the Rajya Sabha and assented to by the President. [Placed in Library. *See* No. LT-1159/90].

(The Deputy Chairman in the Chair)

Ordinance under sub-clause (a> of clause (2) of Article 123 of constitution

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI JAGDEEP DHANKAR): Madam, on behalf of SHRI PARVATHANENI UPENDRA, I lay on the Table under sub-clause (a) of clause (2) of Article 123 of the Constitution, copy each (in English and Hindi) of the following Ordinances: —

(i) The Indian Council of World Affairs Ordinances, 1990 (No. 2 of 1990).

(ii) The Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Ordi ance, 1990 (No. 3 of 1990).